tioned "MP demands probe against UCO Bank" which appeared in Business Standard of 14th February; 1990;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) whether any inquiry has been ordered into the state of affairs of the said bank, if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF FINANCE (PROF. MADHDU DANDAVATE): (a) to (c) Government have seen the news item under the caption "MP demands probe against UCO BANK" appearing in Business Standard of 14th February, 1990. The Press Report, *inter-alia* mentions about the alleged critical financial position of the banks.

As per the published annual accounts of the UCO Bank as at the end of March, 1989, the bank had earned a profit of Rs. 573 lakhs. Besidhes, there was improvement in the major areas of operations of the bank. The bank's aggregate deposits in India which stood at Rs. 3129 crores as at the end of December, 1986 rose to Rs. 4982 crores as at the end of March, 1989. Similarly, the net domestic credit of the bank which was Rs. 1724 crores as at the end of December, 1986 increased to Rs. 2663 crores as at the end of March, 1989.

The operations of public sector banks are continually reviewed by the Government and the Reserve Bank of India. R.B.I. has recently conducted annual financial review of the bank. The financial position of the bank has also been periodically reviewed by Governor, Reserve Bank of India during the Action Plan meetings.

इस्पात पर अत्यधिक लेवी

2041. **श्री राम जेठमलानी:**

सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जनवरी, 1990 के "डेक्कन हेराल्ड" में "माल्टीपल लेवीज मेक स्टील कोस्टली; सी०ई०आई० स्टडी" शीर्षक से प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकारी करों के कारण इस्पात के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उत्पादन, परिवहन प्रशासनिक व्यय और सरकारी व्यय की अलग-अलग लागत के संबंध में इसका अनुमानित प्रतिशत कितना है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) :(क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) मुख्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित कुछ मदों के मूल्यों को संयुक्त संयंत्र समिति जो उत्पादनों की एक संस्था है, द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जाता है, ताकि कोयले, बिजली, रेल-भाड़े आदि जैसे आदानों की लागत में हुई वृद्धि को निष्प्रभावित किया जा सके । उत्पाद-शुल्क की दरों में संशोधन से भी अन्तिम मूल्य प्रभावित होते हैं । 1989 के दौरान मूल्यों में तीन बार वृद्धि की गई। यह वृद्धि जनवरी 89 में औसतन 7.6 प्रतिशत लागत - वृद्धि के कारण मार्च, 1989 में 2.1 प्रतिशत उत्पाद शुल्क में वृद्धि के कारण तथा रेल-भाड़े में वृद्धि के कारण 1.5 प्रतिशत की गई । संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा घोषित लोहे और इस्पात मदों के विक्रय मूल्य इन लागतों के अलावा भाड़ा एकीकरण और इस्पात विकास निधि जैसी लेवी पर भी निर्भर करते हैं । ये उत्पादन लागत से संबंधित नहीं होते अपितु उपभोक्ताओं और मुख्य उत्पादकों की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हैं ।